अपनी बात

तिब्बत मामले पर चीन की संयुक्त राष्ट्र में आलोचना सराहनीय

तिब्बत में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। चीन की उपनिवेशवादी दमनात्मक नीति के कारण वहाँ मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। तिब्बती अपने देश में ही कैदी बने हुए हैं, क्योंकि चीन का तिब्बत पर अवैध कब्जा है। समस्या का अंतिम समाधान है तिब्बत की चीन से आजादी।

तिब्बती गत कुछ महीनों से तिब्बत में और तिब्बत के बाहर भी चीन सरकार की क्रूरता से तंग आकर अपने ही हाथों अपने शरीर में आग लगा रहे हैं। झुलस रहे हैं। आत्मबलिदान कर रहे हैं। आत्मदाह कर रहे हैं। देश की आजादी के लिए आत्मदाह का तरीका विचलित करने वाला है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के लगातार अनुरोध के बावजूद आत्मदाह की घटनाओं का जारी रहना चिंताजनक है तथा दुर्भाग्यपूर्ण भी। दलाई लामा जी तथा तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री (सिक्योंग) डॉ. लोबजंग संग्ये तिब्बत की बुरी दश से भलीभाँति परिचित हैं। वे यह भी जानते हैं कि कई तिब्बती बहुत ही लाचारी में आत्मदाह का निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि चीन सरकार का अमानवीय आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर भी तिब्बत समर्थक संगठनों, व्यक्तियों एवं महत्वपूर्ण तिब्बती नेताओं की अपील है कि आंदोलनकारी आत्मदाह जैसा पीड़ादायक कदम मत उठायें। उन्हें अपना अहिंसक आंदोलन जारी रखना चाहिये। वे आत्महिंसा भी मत करें।

आत्मदाह के मामले में चीन की सरकार उल्टे चोर कोतवाल को डाँटे की तर्ज पर चल रही है। वह परमपावन दलाई लामा, डॉ. लोबजंग संग्ये तथा अन्य सभी तिब्बत समर्थक संगठनों को ही आत्मदाह के लिए दोषी ठहरा रही है। उसके अनुसार ये ही तिब्बतियों को आत्मदाह के लिए प्रेरित–प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके अनुसार विश्वस्तर पर चीन को बदनाम करने की यह सोची समझी साजिस है। यह प्रसन्नता की बात है कि चीन सरकार की असलियत सामने आ गई है। तिब्बत में उसके द्वारा चलाई जा रही उत्पीड़न एवं विनाष की नीति की कलई खुल चुकी है।

संयुक्त राष्ट्र में अभी ग्यारह देशों ने चीन में मानवाधिकारों की स्थिति को चिंताजनक बताया है। उनके अनुसार पूरे चीन में और विशेषकर चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए तिब्बत में मानवाधिकारों का व्यापक पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। तिब्बती मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। उन्हें अवैध तरीके से चीन की सरकार बंदी बना रही है। उन्हें अमानवीय यातनायें दी जा रही हैं। इन देशों के अनुसार तिब्बत में चीन सरकार प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर रही है। पर्यावरण के मानदंडों की उपेक्षा करते हुए वहाँ जल, जंगल, जमीन, पहाड़ तथा खदानों का विनाश कर रही है। इससे पूरे विश्व, विशेषकर एशिया महादेश और उसमें भी भारत के लिए संकट गहराता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा होनी चाहिए, तभी वे भविष्य में भी काम आ सकेंगे। लेकिन चीन सरकार भोगवादी होने के कारण तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अपने अनियंत्रित लालच को पूरा करने हेतु कर रही है।

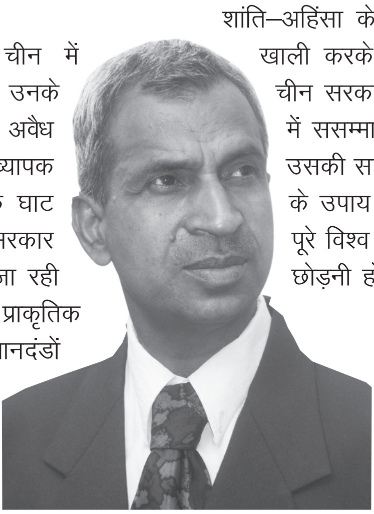

तिब्बत में आध्यात्मिक मठ–मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उन्हें चीन का प्रशासन अपवित्र तथा अपमानित कर रहा है। बौद्ध ग्रंथ फाड़े–फेंके जा रहे हैं। आध्यात्मिक प्रतीकों को नष्ट किया जा रहा है। अनेक बौद्ध भिक्षु अवैध तरीके से जेलों में कैद कर लिए गये हैं। हाल ही सौ से अधिक बौद्ध भिक्षुओं ने तिब्बत में प्रदर्शन करके मांग की है कि बेवजह गिरफ्तार किए गए बौद्ध भिक्षुओं को चीन सरकार अविलम्ब रिहा करे तथा झूठे मुकदमे समाप्त करे।

तिब्बत समर्थकों के लिए अच्छी बात है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में ग्यारह देशों ने चीन के दलाई लामा तथा तिब्बत की निर्वासित सरकार के संबंध में लगाए जा रहे मनगढ़ंत आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। इससे चीन की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। इसी प्रकार स्पेन की अदालत में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिंताओ के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उनके खिलाफ आरोप है कि उनके कार्यकाल में तिब्बत में मानवाधिकारों का षड्यंत्रपूर्वक सुनियोजित तरीके से हनन किया जा रहा था। हु जिंताओ यदि स्पेन की यात्रा करें, तो उन्हें वहाँ गिरफ्तार भी किया जा सकता है। यह चीन के लिए शर्मनाक स्थिति है।

चीन सरकार को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, लोकतांत्रिक मर्यादा तथा विश्वजनमत का सम्मान करते हुए तिब्बत में मानवाधिकारों की सुरक्षा के उपाय करे। निर्वासित सरकार और दलाई लामा सार्वजनिक रूप से मांग कर रहे हैं कि चीन की सरकार तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान कर दे। वे वास्तविक स्वायत्तता से संतुष्ट हो जायेंगे। चीन के संविधान में भी ऐसी स्वायत्तता का प्रावधान है। चीन सरकार को यह मांग मान लेनी चाहिए। अन्यथा भविष्य में तिब्बती आंदोलन शांति–अहिंसा के मार्ग से भटक भी सकता है। तब चीन को तिब्बत खाली करके जाना होगा। तिब्बत फिर से आजाद होकर रहेगा। चीन सरकार के लिए उचित है कि वह दलाई लामा की तिब्बत में ससम्मान वापसी के उपाय करे। निर्वासित सरकार के साथ उसकी सार्थक वार्ता हो। तिब्बत के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय किए जायें। इससे तिब्बत के साथ ही चीन का और पूरे विश्व का कल्याण होगा। चीन सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़नी होगी। तभी तिब्बत समस्या का हल निकलेगा। ◆

प्रो० श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी
(राज.)
E-mail :- shyamnathji@gmail.com

दलाई लामा ने कहा, धर्मनिरपेक्ष नीति से ही हल हो सकता है तिब्बत का मसला

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 24 अक्टूबर)

गत 21 अक्टूबर को दलाई लामा ने न्यूयॉर्क शहर में तीन दिवसीय धार्मिक उपदेश कार्यक्रम संपन्न किया। इसमें करीब 24 चीनी विद्वान, लेखक और कवि शामिल हुए। उनकी इस कार्यक्रम में कोई राजनीतिक या चीन–तिब्बत संबंधी मसला नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष नीति पर चर्चा हुई।

दलाई लामा ने मार्क्सवाद में निहित समानता के आदर्श की तारीफ की, ले. किन उन्होंने कहा कि इस विचारधारा के आधार पर सत्ता में आए लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। आधुनिक चीन में नीतिगत मूल्यों ह्रास की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि माओ त्से तुंग जब यन्नान के कॉफी हाउस से बाहर निकलकर काम करे लगे तो ऐसा लगा कि वह असली मार्क्सवाद से प्रेरित हैं, लेकिन 1955–56 के बाद तो वह पूरी तरह सत्ता प्रेरित हो गए। उन्होंने कहा कि चीन अब लगातार भौतिकवादी होता जो रहा है जिसमें समाजवाद ही पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त्र कर रहा है और वहां भौतिकवाद की चरम भूख ने आंतरिक मूल्यों को खत्म कर दिया है। दलाई लामा ने कहा कि भौतिक विकास से ही समाज की सभी बुराइयां दूर नहीं की जा सकतीं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि चीन में न तो लोकतंत्र आया, न आज़ाद प्रेस और न ही ऐसी न्यायिक प्रणाली जो अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप हो।

दलाई लामा ने कहा कि नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में धर्म की भूमिका होती है, उन्होंने यह उदाहरण दिया कि ताइवान जहां की धर्म का संरक्षण होता है, वहां नैतिक मूल्यों का उतना क्षरण नहीं हुआ है जितना कि चीन में। हालांकि, सिर्फ धर्म को बढ़ावा देने पर निर्भर रहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के हर सात में से एक व्यक्ति को धर्म में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पुस्तक "बियांड रिलीजंस–एथिक्स फॉर अ होल्ड वर्ल्ड" का मूल यह है कि धर्मनिरपेक्ष मूल्य ही एक ज्यादा शांति प्रिय दुनिया बनाने का आधार है। इसके लिए सिर्फ सभी धार्मिक परंपराओं के विचार ही नहीं, बल्कि जो लोग कोई धर्म नहीं मानते उनके विचारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। दलाई लामान ने कहा कि वह पूर्व चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ के इस आह्वान का समर्थन करते हैं कि समाज को और सौहादपूर्ण बनाया जाए, लेकिन उन्होंने जिनताओ ऐसा समाज बनाने में इस वजह से विफल रहे क्योंकि उन्होंने इसे हासिल करने के लिए ताकत के इस्तेमाल का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राष्ट्रपति शी जिन. पिंग उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं, जहां हू विफल रहे और इसके लिए उन्हें तिब्बतियों जैसे सभी लोगों की संस्कृति, भाषा और धर्म को बराबर का सम्मान देना होगा।

दलाई लामा ने कहा, "सौहार्द और एकता की भावना भरोसे पर निर्भर होनी चाहिए...और भरोसा सिर्फ दोस्ताना लगाव दिखाने से बनता है। डर असल में भरोसे का विपरीत है और भरोसे के बिना को. ई एकता नहीं हो सकती। सौहार्द सिर्फ खाने–पीने के प्रावधान करने से नहीं हासिल किया जा सकता, यह दिल से आना चाहिए। इसलिए इसके लिए रवैया बदलना होगा।" ◆

साथी तिब्बती भिक्षुओं की रिहाई की मांग को लेकर सैकड़ों भिक्षुओं का प्रदर्शन

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 16 अक्टूबर, 2013)

सिचुआन प्रांत के कार्जे प्रशासनिक क्षेत्र के एक मठ से जुड़े सैकड़ों भिक्षुओं ने स्थानीय पुलिस थाने तक जुलूस निकालकर अपने एक साथी भिक्षु की रिहाई की मांग की। रेडियो फ्री एशिया की 14 अक्टूबर की खबर के मुताबिक उक्त तिब्बती को इस आरोप में हिरासत में ले लिया गया है कि उन्होंने एक हफ्ते पहले तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के अपने गृह प्रशासनिक क्षेत्र में पुलिस के प्राणघातक दमन के खिलाफ कथित रूप से आवाज उठाई थी। पालयुल काउंटी के पालयुल मठ के भिक्षु केलसांग छोडार को स्थानीय पुलिस द्वारा 12 अक्टूबर को सुबह 8 बजे हिरासत में लेने के तत्काल बाद यह जुलूस निकाला गया। पालयुल से जुड़े करीब 400 भिक्षु जुलूस निकालकर पुलिस थाने तक गए और उन्होंने हिरासत में लिए भिक्षु को रिहा करने की मांग की।

हिरासत में लिए गए भिक्षु मूल रूप से नागछू प्रशासनिक क्षेत्र के सोग (सुओ) काउंटी के थे और फिलहाल वह पलयुल में अध्ययन कर रहे थे। चीनी पुलिस उन्हें इस संदेह में उठाकर ले गई थी कि वह पड़ोस के सॉग काउंटी के नागछू ड्रिरू काउंटी में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बारे में सूचनाएं फैला रहे हैं। असल में ड्रिरू में तब विरोध प्रदर्शन को हवा मिली थी, जब चीन सरकार ने सभी तिब्बतियों को यह आदेश दिया था कि वे अपने घरों और मठों की छतों पर साम्यवादी चीन का लाल झंडा लगाएं और इस पर सितंबर माह से ही विरोध प्रदर्शन जारी है। गत 6 अक्टूबर को चीनी अर्द्ध सैनिक बलों ने तिब्बती विरोध प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी थी जिसे चार लोग मारे गए थे और कम से कम 50 लोग घायल हो गए थे। इसके साथ ही तिब्बतियों के विरोध प्रदर्शन पर चीनी दमन बढ़ता ही गया है। हिरासत में लिए गए तिब्बती भिक्षु को कहां रखा गया है, इसकी किसी को जानकारी नहीं मिल पा रही। ◆

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की समीक्षा के दौरान अपनी आलोचना को चीन ने फिर खारिज किया

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 24 अक्टूबर)

स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 22 अक्टूबर, 2013 को दूसरे सार्वभौमिक नियतकालिक समीक्षा के लिए आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानववाधिकार परिषद का समीक्षा सत्र।

गत 22 अक्टूबर को दुनिया के 11 देशों ने चीन से आग्रह किया कि वह तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार करे। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा चीन के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड की दूसरे सार्वभौमिक नियतकालिक समीक्षा (यूपीआर) में यह आग्रह किया गया है। उन्होंने हवाला दिया कि तिब्बत में धा. र्मिक आज़ादी, अल्पसंख्यक अधिकारों की कमी है और वहां तिब्बत के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने चीन से अनुरोध किया कि दलाई लामा के सार्थक वार्ता शुरू करे। चीन ने सभी आलोचनाओं को पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि देश से बाहर का कोई व्यक्ति उसके रिक. ॉर्ड की समीक्षा नहीं कर सकता।

तिब्बत में चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करने वाले देशों में कनाडा, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका और आइसलैंड शामिल हैं।

उन्होंने सुझाव दिया कि चीन को तिब्बतियों–साथ ही उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के पालन करने पर सताना बंद करना चाहिए, उनके खिलाफ सभी असंगत नीतियां बंद कर देनी चाहिए, अहिंसक व संवाद के रास्ते से उनके असंतोष को दूर करना चाहिए, उनके सांस्कृतिक अधिकारों व धार्मिक आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए, सभी जातीय अल्पसंख्यकों के सदस्यों की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, तिब्बत सहित सभी अल्पसंख्यक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को निर्बाध तरीके से जाने देना चाहिए और तिब्बत मसले पर दोतरफा संवाद शुरू करना चाहिए।

अपने अंतिम जवाब में, चीन ने इन सभी आलोचनाओं को खारिज करते हुए दावा किया कि किसी को भी चीन में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में पता नहीं है। चीन का कहना है कि उसके यहां मानवाधिकारों की स्थिति बेहतरीन है और दूसरे सरकारों से बेहतर है। अपने जवाब में चीन ने कहा है, "कुछ देशों ने नागरिकों की रक्षा के लिए किए जाने वाले सुरक्षा बलों की कार्रवाई की तुलना नस्लीय सफाए से की है और चीन के कई अपराधियों को मानवाधिकारों का रक्षक बताया है। सामान्य न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक अभियोग बताया गया है। यह मानवाधिकारों का राजनीतिकरण है. ..चीन में मानवाधिकारों के बारे में सबसे अच्छी जानकारी कोई रखता है तो वह चीनी नागरिक हैं।"

हालांकि, नवंबर में होने मानवाधिकार परिषद के चुनाव में अपने बेहतर मौके के लिए चीनी दूत वु हाइलोंग ने कहा कि मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के लिए उनके देश का सालाना चंदा अगले चार साल में 50,000 डॉलर से बढ़ाकर 8 लाख डॉलर तक किया जाएगा। इसके पहले चीन 2006 से 2012 तक परिषद का सदस्य था।

संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की नियकालीन समीक्षा की जाती है। इस बार समीक्षा का नेतृत्व पोलैंड, सियरा लियोन और संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। इस गैर बाध्यकारी समीक्षा प्रक्रिया में इस बात पर भी जोर दिया गया कि चीन की संसद नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों (आईसीसीपीआर) के अंतरराष्ट्रीय अनुबंध को अनुमोदित करने में विफल रही है।

वु राजनीति एवं धार्मिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वह कुछ समस्याओं को रेखांकित करते हैं। उन्होंने कहा, "न्यायिक अन्याय अब भी मौजूद है। इसके अलावा उनकी सरकार को गरीबी, स्वास्थ्य की कमी और पर्यावरण मसले का समाधान करना है।"

हालांकि, मानवाधिकारों के मसले पर चीन की तारीफ करने वाले भी कई देश मिल मिल गए हैं, लेकिन ये ऐसे देश हैं जिनमें से ज्यादातर दुनिया में मानवाधिकारों के मामले में सबसे खराब रिकॉर्ड वाले हैं। इन देशों में शामिल हैंः ईरान इस्लामी गणतंत्र, क्यूबा, रूस, वेनेजुएला, यमन, जाम्बिया, जिम्बाबवे, अफगानिस्तान, कांगो, लेबनान, सिंगापुर और चिली। कुछ देशों की तारीफ तो चकित करने वाली है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान जिसने कहा, "परिषद की सिफारिशों को लागू करने के लिए चीन द्वारा उठाए गए कदमों की हम सराहना करते हैं।" सच तो यह है कि चीन ने पहले परिषद द्वारा सुनवाई में की गई लगभग सभी सिफारिशों को साफतौर से और विद्रोही तरीके से खारिज किया है। ◆

मैक्सिको में दलाई लामा के उपदेा और सार्वजनिक व्याख्यान में सैकड़ों लोग भाामिल हुए

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 14 अक्टूबर)

मैक्सिको के सैन क्रिस्टोबाल में 15 अक्टूबर को परंपरागत मैक्सिकन चारो हैट पहने हुए परमपावन दलाई लामा, साथ में मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति वाइसेंटे फॉक्स भी दिख रहे हैं।

दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको के अपने छह दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन 12 अटूबर को तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने एक धार्मिक उपदेश दिए और उन्होंने वे. टिकन होली सी द्वारा स्थापित पोंटिफिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में व्याख्यान भी दिया। इन दोनों कार्यक्रमों में हजारों लोग शामिल हुए। इस यात्रा के दौरान उनकी किसी भी राजनीतिक नेता से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं था। दलाई लामा ने मै. क्सिको के एरेना सिउडाड डी मैक्सिको में धार्मिक उपदेश दिया जहां लोगों को उनसे रू–ब–रू कराने का काम हॉलीवुड स्टार और लंबे समय से तिब्बत आंदोलनकारी रहे बौद्ध धर्म का पालन करने वाले रिचर्ड गेरे ने किया। दलाई लामा ने आठवीं सदी के भारतीय गुरु शांतिदेवा के ग्रंथ "बौद्ध जीवन पद्धति के बारे में एक मार्गदर्शक" पर आधारित उपदेश दिए।

दलाई लामा ने बौद्ध धर्म और उसकी विभिन्न परंपराओं के बारे में एक समग्र दृष्टि के साथ अपने उपदेश की शुरुआत और विस्तार की और उन्होंने आज की दुनिया के अंतर धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भी प्रस्तुत किया। उपदेश के बीच लंच ब्रेक के दौरान उन्होंने लातिन अमेरिका के 400 साल पुराने मुख्य रोमन कैथोलिक यूनिवर्सिटी का भ्रमण किया।

दलाई लामा ने बताया कि आध्यात्मिक परंपरा दो पहलू होते हैं–पालन और दर्शन और उन्होंने इसकी व्याख्या की कि दुनिया के विभिन्न संप्रदायों में पालन के मामले में बहुत कुछ समान है जैसे प्यार और करुणा, सहिष्णुता और संतोष पर जोर। इस अवसर पर एक शिलापट्ट का भी अनावरण किया गया जो कि इस दौरे की स्मृति के लिए विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह धार्मिक कार्यक्रम 12 से 14 अक्टूबर तक चला।

दलाई लामा ने 13 अक्टूबर को 'धर्म से परेः समूची दुनिया के लिए नैतिक मूल्य' विषय पर एक सार्वजनिक व्याख्यान भी दिया और इसी जगह पर 14 अक. टूबर को छात्रों को 'समकालीन शिक्षा में मानव मूल्य' विषय पर संबोधित किया। इसके बाद 15 अक्टूबर को उन्होंने लियोन के सैन क्रिस्टोबाल स्थित सेंट्रो फॉक्स में 'कार्रवाई में करुणा' विषय पर एक सार्वज. निक व्याख्यान को संबोधित किया। जैक्टे. कास शहर में 16 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंसिया मैजिस्ट्राल के कन्वेंशन सेंट में 'खुशहाली की कला' विषय पर एक सार्वजनिक व्याख्यान के साथ ही मैक्सिको में उनके कार्यक्रमों का समापन हुआ। ◆

चीन ने आत्मदाह से हुई एक व्यक्ति की मौत पर तीन तिब्बतियों को जेल में डाला

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 25 अक्टूबर)

सिचुआन प्रांत के नाबा प्रशासनिक क्षेत्र स्थित मारथांग काउंटी की एक चीनी अदालत ने इस साल जनवरी में एक आत्मदाह करने वाले तिब्बती की जलकर मौत के समय पुलिस को रोकने के प्रयास में कथित रूप से अड़चन डालने के प्रयास में तीन तिब्बतियों को पांच साल तक जेल मिली है। रेडियो फ्री एशिया ने 23 अक्टूबर को यह जानकारी दी है। मृत व्यक्ति 28 वर्षीय फुंसोक ने चीनी शासन के विरोध में गत 18 जनवरी को काउंटी थाने के बाहर खुद को आग लगाकर जान दे दी थी। खबर के अनुसार इस साल जुलाई महीने में इन तीनों तिब्बतियों को जेल की सजा सुनाई गई। कुंगोन और सोनम यांगफेल को चार–चार साल की और नोरी दोरजी को पांच साल की सजा सुनाई गई। इन सभी लोगों पर आरोप लगाया गया कि फुंसोक की "मौत उनकी वजह से" ही हुई है। खबर में एक निर्वासित तिब्बती सूत्र के हवाले से बताया गया है कि उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों से अग्निशामक यंत्र छीनने की कोशिश की जो कि फुंसोक के शरीर में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे।

खबर के अनुसार प्रशासन ने तीनों परिवारों के ऊपर कई तरह की प्रक्रियात्मक अड़चनें लगा दी हैं जिससे वे उनसे जेल में जाकर मिल भी नहीं पा रहे हैं। तीनों को पड़ोसी चीनी शहर मियानयांग की एक जेल में कैद किया गया है। ◆

चीनी सुरक्षा बलों की गोलीबारी से चार तिब्बती प्रदर्शनकारी मरे, कई घायल

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 13 अक्टूबर)

मकानों और मठों पर कम्युनिस्ट चीन का लाल झंडा फहराने के आदेश का विरोध कर रहे तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के नागछू प्रशासनिक क्षेत्र के ड्रिरु काउंटी में रहने वाले तिब्बतियों का दमन हिंसक रूप ले चुका है। ऐसे ही दमन की 8 अक्टूबर की एक घटना में तीन गावों में सुरक्षा बलों की गोलीबारी से चार तिब्बती मारे गए हैं और 50 अन्य घायल हो गए हैं। इसके पहले 6 अक्टूबर को भी एक घटना में कम से कम 60 तिब्बती घायल गए थे, जब चीनी सुरक्षा बलों ने एक तिब्बती भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। ये सभी तिब्बती अपने एक साथी तिब्बती की रिहाई की मांग कर रहे थे जिसे एक हफ्ते पहले ही झंडा फहराने के आदेश का विरोध करने की वजह से हिरासत में ले लिया गया था।

रेडियो फ्री एशिया की 11 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार चीनी अर्द्धसैनिक बलों द्वारा विरोध प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की वजह से सेंगथांग गांव में तीन ग्रामीण मारे गए, जबकि टिनरिंग गांव में भी एक तिब्बती मारा गया। इसके अलावा उसकी दिन काउंटी के यांगथांग गांव में विरोध प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई में करीब 50 तिब्बती घायल हो गए।

मारे गए तिब्बतियों का नाम, पता और विरोध प्रदर्शन किसलिए हुआ था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि चीन ने सभी संचार माध्यमों और लोगों की आवाजाही पर सख्त नियंत्रण लगा रखा है। उदाहरण के लिए बताया जाता है कि चीनी पुलिस ने ल्हासा के ऐसे लोगों के फोन को जब्त कर लिया है जिनका ड्रिरू काउंटी के लोगों से कोई संपर्क है। ड्रिरु काउंटी के निवासियों के कहीं आने–जाने पर रोक लगा दी गई है।

धर्मशाला स्थित तिब्बती मानवाधिकार एवं लोकतंत्र केंद्र ने 11 अक्टूबर को बताया कि चौबीसों घंटे निगरानी रखने वाले 'सुविधा पुलिस चौकी' (जुलाई 2012 तक पूरे टीएआर में ऐसी 676 चौकियां स्थापित की गई हैं) के द्वारा नागछू के तिब्बतियों की एक–एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इन चौकियों को तिब्बतियों के बारे में जानकारी का आदान–प्रदान करना होता है। ◆

भारत के साथ सीमापारीय नदियों पर हुए समझौते में तिब्बत के बांधों के बारे में चीन ने नहीं दी जानकारी

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 26 अक्टूबर)

खबर के अनुसार इतने ज्यादा सुरक्षा बलों की तैनाती से बहुत से लोग काउंटी छोड़कर प्रशासनिक क्षेत्र की राजधानी नागछू, ल्हासा और कार्मो जैसी जगहों पर पलायन कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा के दौरान भारत और चीन ने गत 23 अक. टूबर को सीमापारीय नदियों पर सहयोग मजबूत करने का एक समझौता किया। हालांकि, इकनॉमिक्स टाइम्स ऑनलाइन की 25 अक्टूबर की खबर के मुताबिक इस बहुचर्चित यात्रा के दौरान हुआ यह समझौता दुनिया के सबसे ऊंचे बांध (मौजूदा अनुमानों के मुताबिक 3,370 फुट) के बारे में भारत की तात्कालिक चिंताओं का समाधान नहीं करता जो अधिकृत तिब्बत में बनाया जा रहा है।

नए समझौते में बस एक सकारात्मक घटनाक्रम यह हुआ है कि चीन मई से अक्टूबर के दौरान ब्रह्मपुत्र (यारलुंग सांगपो) नदी में बाढ़ के बारे में ज्यादा आंकड़े मुहैया कराएगा। इसके पहले 2008 और 2011 के समझौतों के मुताबिक चीन जून से अक्टूबर के बीच के आंकड़े ही मुहैया करता था।

खबर में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस समझौते से तिब्बत के शन्नान (ल्होका) प्रशासनिक क्षेत्र के जांगमू में बनाए जा रहे पनबिजली (510 मेगावॉट) परियोजना के बारे में भारत की तात्कालिक चिंताओं का समाधान नहीं हो पाया है। इस बांध का निर्माण 2010 से शुरू हुआ है और इसके वर्ष 2015 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चीन इस प्रोजेक्ट से गुआंगडा. ंग और हांगकांग की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा और उसकी योजना म्यांमार, थाइलैंड, बांग्लादेश, लाओस, कम्बोडिया तक बिजली आपूर्ति करने की है। खबर के अनुसार भारत को यह डर है कि इस प्रोजेक्ट से भारत में प्रवेश करने पर नदी जल का प्रवाह घट जाएगा और इससे भारत की तरफ हिमालयी पर्यावरण व्यवस्था का भी विनाश होगा।

सिंह के दौरे के दौरान इस बात पर भी कोई चर्चा नहीं हुई कि साल चीन ने आखिर तीन नए बांध प्रोजेक्ट को मंजूरी क्यों दी, जिसमें से एक की क्षमता तो जांगमू से भी ज्यादा है। इस साल की शुरुआत में चीन ने डागू में बनने वाले 640 मेगावॉट के बांध को मंजूरी दी है जो जांगमू से 18 किमी. दूर है। इसके अलावा जियाचा में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य पहुंच और जांगमू की निचली धारा पर 320 मेगावॉट का एक बांध और जांगमू से ऊपरी धारा की ओर 11 किमी. दूर जिक्सयू में एक बांध बनाने की मंजूरी दी गई है।

खबर के अनुसार चीन इन बांधों के निर्माण के लिए बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। खबर में कहा गया है कि चीन के इस रवैये की वजह से ही इस इलाके में अक्सर मौसम बेहद खराब हो जाता है।

खबर के अनुसार चीन ने यारलुंग सांगपो की सहायक नदियों पर भी कम से कम छह पनबिजली परियोजनाएं बनाई हैं और उसका दावा है कि इसका निचली जलधाराओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत इस बात से बहुत निराश है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रही पनबिजली परियोजनाओं के बारे में जानकारी देने के मामले में चीन ने पारदर्शी रवैया नहीं अपनाया है। ◆

तिब्बत में खनन से एशिया की नदियों को खतरा

(द थर्डपोल डॉट नेट, 12 अक्टूबर 2013)

तिब्बत को औद्योगिक केंद्र में बदलने के लिए गहन खनन की तैयारी की जा रही है जिसका पर्यावरण और समाज पर काफी विनाषक असर होगा, यह कहना है गैब्रिएल लैफिते का।

xfc,y yfQr

अपनी नई पुस्तक 'Likbfyx frCcr% pkbuk ,M jhlkl u'kufyTe vku n :Q vkQ fn oYM^ में गैब्रिएल लैफिते तिब्बत में चीन के खनिज दोहन के पैमाने और विस्तार का विश्लेषण करते हैं।

यहां वे थर्डपोल से तिब्बत पठार के वैश्विक पर्यावरण महत्व और इस क्षेत्र की नदियों एवं उनकी निचली धाराओं पर स्थित देशों पर खनन के असर की चर्चा करते हैं।

fn FkMl ikly ¼VhVhih½% frCcr dk iBkj dk ckjk e ,lh fo'k’k ckr D;k g

xfc,y yfQr% क्या मैं इस सवाल का जवाब एक और सवाल पूछकर थोड़ा ति. रछे तरीके से दे सकता हूं? आखिर उद्योगों द्वारा शताब्दियों तक औद्योगिक जरूरतों के लिए जीवाश्म ईंधन जलाने के बाद ही किसी के मन में यह विचार आया कि इससे जलवायु पर असर पड़ सकता है? यहां तक कि अब भी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी समिति (आईपीसीसी) की कड़ी मेहनत से तैयार सूक्ष्म रिपोर्ट के बाद भी अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यह संदेह है कि मनुष्य के ईंधन उपभोग से इस ग्रह के जलवायु पर कोई असर पड़ रहा है।

आईपीसीसी का गठन 1988 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऐसे समय में किया गया था, जब सभी क्षेत्रीय जलवायु व्यवस्थों की परस्पर निर्भरता और कार्बन ऑक्साइड के बढ़ते स्तर की वजह से उनके बदलने का जोखिम वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट हो गया था। विज्ञान असल में कुछ ऐसी चर वस्तुओं द्वारा जटिलता को कम करता है जिनको नियंत्रित, प्रेक्षित और छेड़ा जा सकता है।

सभी गोचर वस्तुओं में परस्पर निर्भरता तिब्बतियों के लिए कोई नई खबर नहीं है, जो कि हजारों साल से पश्चिमी यूरोप के बराबर के आकार के एक पठार को संभाल रहे हैं, गतिशील सभ्यता के हल्के से स्पर्श के साथ। एक महान पठार पर किसी तरह के बाड़ के बिना वन्य और घरेलू पशु मुक्त रूप से घुल–मिल जो हैं, जहां सबके लिए जगह है, जैव विविधता का संरक्षण बिना कुछ किए ही होता है, बौद्ध लामाओं द्व ारा यह याद दिलाने की भी जरूरत नहीं होती कि शिकार बुरा कर्म है। तिब्बती यह जानते हैं कि उनकी भूमि खनिजों से संपन्न है, लेकिन वे किफायत से खनन करते थे ताकि पृथ्वी के देवता नाराज न हों। वे यह जानते हैं कि उनकी नदियां बहते हुए सभी दिशाओं में इस ऊंचे पठार से काफी दूर जाकर निचली जलधाराओं के पास रहने वाली जनसंख्या की जल की जरूरत पूरी करती हैं।

आज की भाषा में कहें तो वे पर्यावरण सेवा मुहैया करते थे, बिना कुछ किए, अपने पशुओं को लेकर इधर–उधर घूमते रहते थे, ताकि एक जगह पर अतिशय चराई से बचा जा सके। वे जानते थे कि वहां का जलवायु अप्रत्याशित है, अचानक बर्फबारी और ओलावृष्टि गर्मियों में भी हो सकती है, बर्फबारी और भारी बर्फीली हवाएं ऐसे समय में आती हैं, जब वसंत में याक और भेड़ें अपने उच्च पर्वतीय चारागाह की ओर जा रहे होते हैं, या जाड़े में नीचे की तरफ स्थित चारागाह की ओर जा रहे होते हैं। स्वीकार्यता, अनिश्चितता के साथ रहने की क्षमता, चारागाह प्रबंधन में लचीलापन और जोखिम प्रबंधन ऐसे कौशल हैं जिसने तिब्बतियों के पठार को मनुष्य के रहने लायक बनाया है। इस ग्रह के आसमान में स्थित एक महान द्वीप की तरह असाधारण अक्षांश पर रहने वाले तिब्बती जाड़े में पठार की दक्षिणी तरफ जाती तूफानी हवाएं और गर्मियों में इसे उत्तरी छोर पर जाते देखते हैं। हर दिन के अनुभव से तिब्बतियों को वह सब पता है जिसे विज्ञान टेलीकनेक्शन कहता है, सभी जलवायु प्रणालियों को एक ग्रहीय संचार से जोड़ने का।

लेकिन इस ऊर्जा प्रवाह, वायुमंडलीय प्रसार और जल चक्र के गहन, सम्मिलित जानकारी को भूतकाल का क्यों बनाएं? परस्पर निर्भरता की जानकारी अब भी वहां है, यहां तक कि उनके पठार की अनिवार्य रूप से बाड़ेबंदी कर दी गई है और हिरन जैसे वन्यजीव विलुप्त हो गए हैं। घासों, मौसमों, हवाओं और जोखिम की जानकारी का अब भी इस्तेमाल हो रहा है, उन बचे–खुचे इलाकों में जहां चराई की इजाजत दी गई है और अब भी घुमंतू संस्कृति कायम है। नदियों और झीलों की पवित्रता की रक्षा अब भी उन रिवाजों से की जा रही है जिनमें मनमौजी नदियों को नाराज करने के प्रति चेतावनी दी गई है।

VhVhih% D;k vki FkkMk jkekuh ugh gk jg ;g tkrkr g, fd vkt dh nfu;k e budk fy, dkbl txg ugh

तिब्बत की गाइमा घाटी में बड़े पैमाने पर चल रहा खनिज संसाधनों का निष्कर्षण।

cph gS\

xSfcz,y yfQr% ऐसे आधुनिकता से पहले की निर्विवाद समझ के बारे में रोमानी होने या रहस्यवादी होने जैसी कोई बात नहीं है। बौद्ध लोग इसे कर्म फल का नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका साधारण मतलब आम समझ से ही निकाला जा सकता है कि जैसा कर्म होता है वैसा उसका असर होता है।

VhVhih% fuf'pr :i ls frCcr iBkj ds vkdkj dks ns[krs gq, dN [knkuksa ls ogka cgqr T;knk Qdz ugha iMus okykA

xSfcz,y yfQr% तिब्बतियों ने अपनी पर्यावरण सेवाओं के द्वारा जो कुछ भी बचाया है, आज उन सब पर खतरा है। संसाधनों के दोहन के लिए तैयार अंतः क्षेत्रों में तीव्रीकरण, पूंजी, तकनीक और श्रम के संकेंद्रण के अनवरत तर्क, पशुओं के व्यापार या पर्यटकों की खुशी के लिए जमीन का गहन इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े–बड़े इलाकों से जनसंख्या खाली हो जा रही है।

खनन तेजी से तिब्बती पठार को लागत केंद्र से (जहां बुनियादी ढांचे के लिए भारी राशि खर्च करनी पड़ रही है) मुनाफा केंद्र में बदल रहा है जहां ध्यान वहां निकाले जाने योग्य 8 करोड़ टन तांबा और 2000 टन सोने पर है, जिसकी चीनी भू–गर्भ वैज्ञानिकों ने पुष्टि भी कर दी है। इससे तिब्बत मुश्किल से ही शायद दुनिया के सबसे बड़े तांबा उत्पादक चिली की बराबरी कर पाए, लेकिन चीन के नए खदान अगले कई दशकों तक काम करने को तैयार हैं और उन्हें सरकार द्वारा सड़क, रेलवे, संचार, पनबिजली, पाइपलाइन, शहरी ढांचे में निवेश का अच्छा फायदा मिल रहा है। असल में दोहन के पुराने तरीकों की जगह अब ज्यादा मुनाफे के लिए ऐसे विकास की जरूरत पड़ रही है।

आज के सोने और तांबे की कीमतों से अगर तुलना करें तो तिब्बत में तांबे की बिक्री से चीन की सरकारी खनन कंपनियों को करीब 617 अरब डॉलर का राजस्व हासिल होगा, जिसका लगभग आधा ही उन्हें उत्पादन की लागत के रूप में खर्च करना होगा और इसी तरह सोने की बिक्री से 106 अरब डॉलर का राजस्व हासिल होगा।

इसका नतीजा यह होगा कि तिब्बत पूरी तरह से बदल जाएगा। तांबा–सोने के भंडार के साथ ही चांदी और आमतौर पर सीसा, जस्ता या मॉलिब्डेनेम जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। इन सभी खनिजों की भारी मांग है और इनका दोहन भी साथ–साथ किया जा सकता है। सस्ती मजदूरी, तिब्बत के पठार से बहने वाली नदियों पर बड़ी संख्या में बने बांधों से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पनबिजली, पर्यावरण के नरम कानून और कच्चे माल के तिब्बत में मिल रहे नए–नए स्रोतों का फायदा उठाते हुए चीन दुनिया के कारखाने में तब्दील हो गया है। चीन में काम खूब बढ़ रहा है, उसके समुद्रतटीय इलाकों से लेकर सुदूर आंतरिक हिस्सों तक। चोंगक्विंग और चेंगदू ऐसे विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरे हैं, जहां दुनिया के बड़े से बड़े कॉरपोरेशन नए कारखाने लगा रहे हैं। हो सकता है कि जल्दी ही आपका अगला स्मार्टफोन या टैबलेट तिब्बत से निकलने वाले लीथियम से बनकर आए।

VhVhih% vki u, cMs [kuu dh ckr dj jgs gSa] ysfdu D;k frCcr esa [kuu iqjkuh ckr ugha gS

xSfcz,y yfQr% तिब्बत में खनन कोई नई बात नहीं है, लेकिन तीव्रता, पैमाना और जो पूंजी निवेश किया जा रहा है, वह एक–दो दशक पहले की तुलना में काफी अलग है, जब खनन सतह पर आमतौर

पर निचले इलाकों से आए गरीब प्रवासी लोगों द्वारा किया जाता था, जो पारा और सायनाइड का इस्तेमाल कर नदियों की तलहटी से जलोढ़ सोने के टुकड़े निकालते थे। अक्सर ऐसे खनन को स्थानीय सरकारें भी वित्तीय मदद देती थीं, ताकि नदियों की तलहटी में बड़े–बड़े जाल लगाकर सोना हासिल किया जा सके, और इससे अनजाने में ही चारागाह, नदी तट, मछलियों और पक्षियों के प्रजनन स्थल को नुकसान पहुंचता था। तिब्बती पिछले कुछ दशकों में जमीन पर मौजूद सोने को हासिल करने की विनाशक होड़ देख रहे हैं, जिसकी कभी वे रक्षा करने में गर्व करते थे, उनके पास प्रतिरोध की ताकत नहीं है, उनके विरोध को तत्काल अलगावाद को बढ़ावा देने वाला अपराध और चीन के अस्तित्व के लिए खतरा बता दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उन्हें एनजीओ के गठन या सार्वजनिक तौर पर बोलने से मना कर दिया जाता है। तिब्बत में कोई भी संगठित पर्यावरण आंदोलन नहीं है, जबकि तिब्बती पर्यावरण की बहुत देखभाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि वहां ऐसा करना राजनीतिक रूप से असंभव है। इस समय तिब्बतियों को इस बात की जरूरत है कि दूसरे लोग इस पर बोलें। बहुत से तिब्बती पर्यावरणविद जेल में हैं।

VhVhih% D;k [kuu l frCcr l fudyu okyh ufn;ka dk fupyh ty/kkjkvka ij fLFkr ykxka ij dkbl vlj iM jgk g

xfc,y yfQr% भू–गर्भीय रूप से तिब्बत एक युवा भूमि है जो अभी भी उभर रहा है। वहां की चट्टानें अक्सर ढीली होती हैं जिनमें भूकंप और नदियों की धारा रोक देने वाले भू–स्खलन का जोखिम बना रहता है और इस तरह से अवरूद्ध नदियां अचानक बाढ़ लाकर तबाही भी मचा देती हैं।

जमीन के भीतर पाई जाने वाली चट्टानें तिब्बत में सतह के करीब हैं जिनमें आर्सेनिक होता है और इसी वजह से बांग्लादेश के ज्यादातर कुंओं के जल में आर्सेनिक पाया जाता है।

तिब्बत की नदियों में विषाक्त भारी धातुएं प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, इसलिए नदियों के करीब खनन कार्यों निकला भारी कचरा जमा करने वाले इसके निक्षालित होकर नदियों के जल में हमेशा के लिए मिल जाने और इससे जल हमेशा के लिए विषाक्त हो जाने का खतरा है। तिब्बतियों ने पर्यावरण कानूनों का जो घोर उल्लंघन देखा है, उससे उनके लिए यह मानने की वजह बहुत कम रह गई है कि खनन करने वाली नई कंपनियां किसी खदान से अयस्क भंडार खत्म हो जाने के बाद वहां दशकों और शताब्दियों तक कचरे की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। हिमालय ऐसी कोई प्राकृतिक बाधा नहीं है जैसा कि भारतीय कल्पना करते हैं। नदियां उनको काटकर गुजरती हैं, मानसूनी बादल उनके ऊपर से उड़कर आते हैं और लोग भी इसे हमेशा पार करते रहते हैं। खनन जब समूचे तिब्बत में फैलेगा तो इससे पूरे दक्षिण एशिया पर कई तरह से असर होगा, खासकर उन इलाकों में खनन से जहां चराई पर प्रतिबंध लगाकर लोगों को हटा दिया गया है। इन जगहों पर कहा तो यह गया था कि फिर से और ज्यादा घास उगाई जाएगी, लेकिन लोगों का किसी तरह का प्रतिरोध बचे न रहने की वजह से वहां ज्यादा से ज्यादा खनन कार्य होने लगा। भारत अक्सर ऐसा सोचता है कि वह नदियों के मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऊपर की ओर है, लेकिन तिब्बत से तो वह नीचे की ओर है और वह भी इस बारे में सचेत हो रहा है कि तिब्बत पर बने पनबिजली बांधों और खनन के बीच एक मजबूत रिश्ता है। अयस्कों के सांद्रकों और स्मेल्टर (गलाने वाले) में बड़े पैमाने पर पनबिजली का इस्तेमाल किया जाता है। भारत निचली जलधारा पर होने के नुकसान के बारे में समझने लगा है और वह भी हिमालय पार बहने वाली इन नदियों के पनबिजली क्षमता का दोहन करने की महात्वाकांक्षा रखता है।

VhVhih% D;k [kuu u frCcr dk cckn dj fn;k g

xfc,y yfQr% अभी तक तो नहीं, लेकिन चीजें तेजी से इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हाल के दशकों में छोटे–छोटे स्तर पर जो खनन कार्य हुए हैं वे पर्यावरण के लिए काफी विनाशकारी साबित हुए हैं, हालांकि उनका आर्थिक असर कम हुआ। लेकिन नए बड़े पैमाने के गहन खनन कार्य जिस तरह से शेटोंगोम, ग्यामा और युलांग में पूरी तरह से चल रहे हैं, उनसे खदानों की मालिक सरकारी कंपनियों के पास इतना धन हो जाएगा कि वे तिब्बत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत कर लेंगी, उसे वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ दिया जाएगा जिसके तहत तिब्बत में कारों और कंप्यूटर का निर्माण होगा, उन्हें निर्यात किया जाएगा और दुनिया भर के लोग उन्हें खरीदेंगे। नए खदानों से जब खूब मुनाफा होगा तो इससे और चीनी प्रवासी आकर्षित होंगे जिसके बाद भूमि का दोहन और बढ़ जाएगा।

तिब्बत की भूमि लगातार गहन दोहन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तिब्बत का पठार भूमि का ज्यादा इस्तेमाल तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए गतिशील चारागाह व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अतिशय चराई और भूमि के अवक्रमण शुरू होने से पहले लोग वहां से हट जाते हैं। लंबी और भारी सर्दियों के मौसम की वजह से एक बार जब अवक्रमण देसी वनस्पतियों को नष्ट करना शुरू करता है तो उसे रोक पाना बेहद मुश्किल होता है। अवक्रमण लगातार बढ़ने, नोमैड को सामाजिक रूप से उनके चारागाहों से बाहर कर देने और चराई पर अस्थायी रोक से तिब्बत में भूमि और खाद्य सुरक्षा को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है कि उसे वापस ठीक करना संभव नहीं होगा और इन सबकी वजह से तिब्बत जनसंख्या विहीन मरुस्थलीय घासभूमि में बदल जाएगा, जहां गहन उत्पादन केंद्रों वाले शहर, खदान और उनको जोड़ने वाले राजमार्ग ही बचे रह जाएंगे। एक चेतावनीजनक संभावना सिर्फ तिब्बत के लिए नहीं बल्कि एशिया के उन अरबों लोगों के लिए भी है जो हर दिन तिब्बत से आने वाले जल का सेवन करते हैं।

(गैब्रिएल लैफिते "स्पॉइलिंग तिब्बतः चाइना ऐंड रिसोर्स नेषनलिज्म ऑन द रूफ ऑफ दि वर्ल्ड" के लेखक हैं जिसका प्रकाषन जेड बुक्स द्वारा 2013 में किया गया है) ◆

स्पेन की एक शीर्ष अदालत ने तिब्बत में नरसंहार के लिए हू जिनताओ पर मुकदमा चलाया

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 12 अक्टूबर)

स्पेन के राष्ट्रीय अदालत के एक फौजदारी अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में चीन के पूर्व राष्ट्रपति श्री हू जिनताओ के खिलाफ अभियोग दायर किया है और अधिकृत तिब्बत में नरसंहार के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। सह–याची कॉमिटे डी अपोयो अल तिब्बत (सीएटी) ने 10 अक्टूबर को एक बयान में जानकारी दी है। हू 1988 से 92 तक तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख थे और इस दौरान उन्होंने तिब्बती प्रदर्शनकारियों के नरसंहार के आदेश दिए थे। उनके इस कार्य की सर्वोपरि नेता देंग जियोपिंग ने तारीफ की थी और हू को तरक्की देकर देश के राष्ट्रपति जियांग जेमिन का उत्तराधिकारी बना दिया गया था।

गत 29 जुलाई को सीएटी ने एक अपील दाखिल की थी जिसके बाद कोर्ट ने हू के लिए परवाना जारी किया। इसके पहले 11 जून को भी सीएटी ने इस बारे में याचिका दायर की थी, लेकिन तब जज इस्माइल मोरेनो ने इसे खारिज कर दिया था। अधिकृति तिब्बत में नरसंहार के आरोपी चीनी नेताओं में हू का नाम सबसे ऊपर है। इनमें पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन और पूर्व प्रधानमंत्री ली पेंग सहित कई पूर्व नेता शामिल हैं।

हू पर अभियोग दायर कर अदालत ने स्पेन के सरकारी वकील के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यह मामला इस आधार पर बंद कर देना चाहिए कि इसका देश से कोई लेना–देना नहीं है। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि वादियों में से एक पीड़ित तिब्बती स्पेन का नागरिक है। अदालत असल में सम्माननीय थुबटेन वांगछेन का हवाल दे रहा था जो बर्सिलोना के फाउडेंशन कासा डेल तिब्बत के निदेशक हैं। अदालत ने सरकार से कहा कि आगे वह इस तरह का तर्क न दे।

जज मोरेनो वर्ष 2006 से ही इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सरकारी वकील ने इस आधार पर भी मामले को बंद करने की अपील की कि इसके बारे में सक्षम न्यायालय चीनी न्यायिक व्यवस्था के तहत हो सकता है जहां वादी को जाना चाहिए। लेकिन अदालत ने इस तर्क को भी खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि चीनी प्रशासन ने उन तथ्यों की किसी तरह की जांच शुरू की हो जिनके बारे में मुकदमा किया गया है।

इसके पहले हू पर अभियोग दर्ज नहीं किया जा सका था क्योंकि एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उन्हें राजनयिक छूट हासिल थी। दस साल तक पद पर रहने के बाद मार्च 2013 में हू ने चीन के पांचवीं पीढ़ी के नेताओं को रास्ता देते हुए कुर्सी छोड़ दी थी। सीएटी ने कहा कि इस अभियोग के साथ ही उसने तिब्बती पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ किए इस वायदे को पूरा किया है कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तिब्बत में बर्बर दमन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति को कानून के चौखट तक नहीं ला देते।

सीएटी ने अपने बयान में कहा है कि शुरुआती अभियोग में ही, अदालत में दिए गए साक्ष्यों और गवाहियों तथा अंतरराष्ट्रीय तिब्बत अभियान (आईसीटी) और ह्यूमन राइट्स लॉ फाउंडेशन द्वारा पेश विशेषज्ञ निष्कर्षों से यह स्थापित हो गया था कि हू जिनताओ जिम्मेदार हैं और उन पर तिब्बत में किए गए अंतरराष्ट्रीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। यह अपराध उन्होंने न केवल तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में 1988 से 1992 के बीच पार्टी के महासचिव रहने के दौरान किया था, बल्कि 2003 में चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका अपराध बनता है क्योंकि "तब वह पार्टी और देश दोनों के सर्वोच्च नेता थे।"

सीएटी के अनुसार न्यायाधीशों ने कहा कि हू पर मामला चलाने और अभियोग दर्ज करने का उनका निर्णय "चीनी नेताओं द्वारा तिब्बत देश और वहां की जनता पर चीनी नेताओं द्वारा किए गए दमन के बारे में अंतरराष्ट्रीय साक्ष्यों पर आधारित है। चीनी अधिकारियों ने लगातार ऐसी समन्वित कार्रवाई का निर्णय लिया जिसका उद्देश्य तिब्बत देश की विशिष्टताओं और वहां की संस्कृति को खत्म करना था। इसके लिए सैनिक शासन लगाने, लोगों के जबरन स्थानांतरण और नसबंदी अभियान, बागियों को प्रताड़ित करना और बड़े पैमाने पर तिब्बत में चीनियों का जबरन स्थानांतरण ताकि धीरे–धीरे वे वहां हावी हो जाएं और देश के स्थानीय मूल निवासियों को खत्म कर दें।"

स्पेन की अदालत के आदेश की आलोचना करते हुए चीन ने नरसंहार के आरोपों पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है। आस्ट्रेलिया के स्काई न्यूज डॉट कॉम के 11 अक्टूबर की खबर के अनुसार चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ छुनयिंग ने बीजिंग में अपने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "तिब्बत चीन का एक अभिन्न हिस्सा है। इस क्षेत्र में जो भी होता है वह चीन का 'घरेलू' मामला है।"

रेडियो फ्री एशिया (वाशिंगटन) की 11 अक्टूबर की खबर के अनुसार हुआ ने कहा कि स्पेन की अदालत का यह प्रयास "चीन सरकार पर हमला और चीन एवं स्पेन के बीच बने दोस्ताना संबंधों में क्षतिग्रस्त करने का है।" उन्होंने "तिब्बत संबंधी मामलों के बहाने किसी भी देश या किसी व्यक्ति के चीन के घरेलू मामलों में दखल देने" का सख्ती से विरोध किया। ◆

तिब्बत में आत्मदाहः पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक

पॉल मूनी
(फोर्ब्स डॉट कॉम, 28 अक्टूबर, 2013)

फरवरी, 2009, नाबा के कीर्ति मठ के एक युवा तिब्बती भिक्षु अपने मठ में प्रार्थना समारोह को निरस्त कर देने से परेशान थे और उन्होंने खुद के शरीर को गैस से भर लिया, चलते हुए एक चौराहे तक गए और खुद को आग लगा लिया। उनके हाथ में घर में ही बनाया गया एक तिब्बती झंडा था जिस पर दलाई लामा का चित्र बना हुआ था। पास में ही मौजूद जन सशस्त्र पुलिस के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और भिक्षु को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस वाले उन्हें उठाकर ले गए। वह बच गए, लेकिन तबसे वह कहां हैं किसी को नहीं पता है।

प्रसिद्ध तिब्बती कवयित्री और टिप्पणीकार सेरिंग वुएजर ने इस घटना का विवरण अपने ब्लॉग पर प्रकाशित किया। अगले चार साल में उन्होंने इस तरह की रिकॉर्ड 126 घटनाओं की रिपोर्ट दी जिसमें चीनी शासन के प्रति असंतोष जताने के लिए तिब्बतियों ने खुद को आग लगा ली। अपनी नवीनतम पुस्तक 'इमोलेशन इन तिब्बतः द शेम ऑफ दि वर्ल्ड' (तिब्बत में आत्मदाहः दुनिया के लिए शर्मनाक) में वुएजर इस दुःखद चलन की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से बताती हैं।

इस पतली सी पुस्तक के फ्रांसीसी अन.ुवाद 'इमोलेशंस ऑ टिबेटः ला हॉंटे ड्यू मॉंडे' में सिर्फ 40,000 फ्रेंच वर्ड है और यह इस साल अप्रैल से जून में लिखी गई है। इसमें वुएजर आत्मदाह के आंकड़े और वजह तथा आत्मदाह करने वालों के अंतिम बयान उपलब्ध करती हैं और उन्होंने इसको विस्तार से बताया है कि चीन इन घटनाओं को किस तरह से ऐसा मोड़ देने की कोशिश कर रहा है जिससे तिब्बत में उनके सरकार के शासन की छवि खराब न हो।

यह मसला काफी संवदेनशील है और चीनियों ने इसे काफी दबाने की कोशिश की है ताकि इस पर चर्चा न हो। वुएजर ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंटों ने उन्हें इस प्रकरण पर कोई किताब न लिखने की चेतावनी दी है, लेकिन इस धमकी को उन्होंने बहादुरी से नजरअंदाज किया है। वह इस बात से काफी नाराज हैं कि चीनी मीडिया आत्मदाह करने वालों की छवि अपराधियों, शराबियों, जुआड़ियों और पागल, वेश्या या "दलाई गुट" (चीन सरकार द्वारा दलाई लामा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला अपमानजनक शब्द) द्वारा बरगलाए गए लोगों के रूप में पेश करती है। वुएजर का कहना है कि तिब्बती आत्मदाह करने वालों को अपना हीरो मानते हैं, उनकी तस्वीरें घरों और मठों में सम्मान के साथ लगाई जाती हैं और उनकी तारीफ में गीत लिखे जाते हैं।

ये घटनाएं तिब्बती समाज के हर वर्ग से हो रही हैं। वुएजर ने जिन 125 आत्मदाह का रिकॉर्ड तैयार किया है उनमें से 104 लोगों की मौत हो गई है। वर्ष 2009 में आत्मदाह का एक मामला, 2011 में 14 मामले, 2012 में 86 मामले और 2013 में अब तक 25 मामले सामने आ चुके हैं। आत्मदाह करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र 64 साल और सबसे युवा की 16 साल थी। इनमें 106 मर्द, 18 औरतें थीं जिनमें 21 पिता और 10 मांएं थीं। इनमें 42 धार्मिक लोग थे जिनमें तीन रिनपोछे या पुनर्जन्म वाले लामा, 63 चरवाहे, तीन मजदूर, एक बढ़ई, ब्लॉगर, कलाकार, टैक्सी ड्राइवर, वनकर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यकर्ता था। इनमें मिडल स्कूल की तीन छात्राएं और एक छात्र भी थे।

इस पुस्तक का सबसे मार्मिक हिस्सा उन 46 अंतिम बयानों का विश्लेषण है, जो वुएजर ने इकट्ठा किया है, जो आत्मदाह करने वालों के इरादों की साफ झलक देता है। इन बयानों में कुछ में तो सिर्फ चंद शब्द ही हैं, जिनमें हाथ से लिखे नोट, रिकॉर्डिंग और रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया मौखिक बयान शामिल है। लोगों को आत्मदाह करते देखने वाले राहगीरों के अनुसार करीब 50 ने जलते समय भी राजनीतिक नारे लगाना नहीं छोड़ा, जैसे "तिब्बत मुक्त होगा", "परमपावन दलाई लामा को तिब्बत लौटने की इजाजत दो" और "तिब्बतियों को स्वाधीनता दो"।

चीन सरकार ने दलाई लामा पर आरोप लगाया है कि वह तिब्बत को चीन से अलग करने के लिए आत्महत्या के इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वुएजर इनको खारिज करते हुए कहती हैं कि आत्मदाह असल में तिब्बत में धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के इधर तेजी से बढ़े दमन का नतीजा हैं। उन्होंने बताया कि मठों में निगरानी करने के लिए सरकारी कर्मचारी थोपे जा रहे हैं, लोगों को जबरन तथाकथित "देशभक्तिपूर्ण शिक्षा" हासिल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, भिक्षुओं को सार्व.जनिक तौर पर दलाई लामा की आलोचना करने को मजबूर किया जा रहा है, पर्यावरण बचाने के बहाने नोमैड को उनके चारागाह भूमि से जबरन हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मठों में जबरन चीन का राष्ट्रीय झंडा और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की तस्वीरें लगाने को मजबूर किया जाता है, जबकि अत्यंत सम्मानित तिब्बती आध्यात्मिक नेता की तस्वीर जब्त करने के लिए घर–घर तलाशी ली जाती है। सौम्य दिखने वाली वुएजर जब भी तिब्बत की राजधानी ल्हासा जाती हैं, तो सरकारी जासूस उनके पीछे लग जाते हैं। उन्हें कई बार बीजिंग स्थित उनके मकान में नजरबंद कर दिया जाता है।

कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी आत्मदाह की आलोचना करते हुए उसे बौद्ध मान्यता

तस्वीरों में आग की लपटों दिख रहे गवांग नॉर्पेल और तेनजिन खेदुप, दोनों ने 20 जून, 2012 को पूर्वी तिब्बत के युशूल में आत्मदाह कर लिया था।

के विपरीत बताते हैं, लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि चीन ने 1963 में वियतनाम में एक बौद्ध भिक्षु के आत्मदाह की खुलकर तारीफ की थी। उक्त बौद्ध भिक्षु ने वियतनाम में चीनी दखल के विरोध में यह आत्मदाह किया था। वुएजर ने कहा कि पहले तो वह इस चलन के बारे में कुछ बोलने के बारे में काफी सचेत थीं क्योंकि इससे उनकी आलोचना का डर था कि वे आत्मदाह को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगीं तो वह इस बारे में प्रखर तरीके से बोलने को मजबूर हुईं। उन्होंने आत्मदाह के अहिंसक स्वरूप पर जोर दिया और यह भी कहा कि किसी ने भी अपने अंतिम बयान में किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं जताया है, जिस बिंदु को पुस्तक के कवर में भी रेखांकित किया गया है।

फ्रांसीसी प्रकाशक इंडीजीन ने जब वुएजर से यह पुस्तक लिखने को कहा तो उन्होंने प्रख्यात और मुखर कलाकार अइ वेइवेइ से इसका कवर डिजाइन करने को कहा। वेइवेइ ने हल्के नारंगी रंग की लपटों वाली कवर बनाई है जिसके सफदे पृष्ठभूमि में आत्मदाह करने वालों के नाम उत्कीर्ण हैं। उनका कहना है कि शैलीगत लपटें अहिंसक हैं और ऐसी नहीं हैं जो लोगों को डराएं। वुएजर कवर को एक खाता (पवित्र तिब्बती स्कार्फ) की तरह ही पवित्र समझती हैं और कहती हैं कि यह उन तिब्बतियों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया है।

उन्होंने कहा कि चीन सरकार आत्मदाह की वजहों को स्वीकार करने से बच रही है और इसकी जगह अपनी बर्बर नीतियां बढ़ाती जा रही है। उन्होंने इसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हुए माओ–त्से–तुंग द्वारा कभी कहे गए इस प्रसिद्ध कथन को उद्धृत किया: "जहां भी दमन होता है, प्रतिरोध वहीं होता है।" वह लिखती हैं, "लोगों को यह जरूर समझना चाहिए कि आत्मदाह विरोध का एक तरीका है।" वह लिखती हैं, "और जब तक इसकी वजह दूर नहीं की जाएगी, लोग विरोध करते रहेंगे।"

उन्होंने कहा कि बर्बर पुलिस और विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई ने लोगों के सामने अपनी भावनाओं को इजहार करने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है और इसकी वजह से लोग अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए ज्यादा चरम तरीका अपना रहे हैं।

ल्हासा से फोन से मुझसे बात करते हुए उन्होंने कहा, "ऐसे कठोर दमन और दमित लोगों के लिए किसी तरह का विकल्प न बचने की वजह से बहादुर तिब्बतियों के लिए सबसे मजबूत विकल्प यही बचा है कि आत्मदाह का रास्ता अपनाएं।" वुएजर ने बताया है कि किस तरह से पुलिस आत्मदाह करने वाले लोगों और उनके रिश्तेदारों को निशाना बना रही है, कुछ को जेल की सजा सुनाई गई है और एक व्यक्ति को तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एक और व्यक्ति को इन घटनाओं की खबर चीन से बाहर पहुंचाने के लिए सजा दी गई है।

वह लिखती हैं, "ऐसे दबाव की वजह से आत्मदाह के बारे में खबरें कई दिन बाद या कई बार महीनों बाद आती हैं। यह बिल्कुल संभव है कि तिब्बती इलाकों में हुई आत्मदाहों की संख्या उससे बहुत ज्यादा हो जो बाहरी दुनिया जानती है।"

उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आत्मदाह किया है उसमें से शायद ही किसी ने अंतरराष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करने के लिए ऐसा किया है, बल्कि उन्होंने तिब्बती जनता को जागरूक करने और चीनी नेतृत्व पर अपनी नीतियां बदलने का दबाव डालने के लिए ऐसा किया है। हालांकि, वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय की निष्क्रियता की भी आलोचना करती हैं। वह वियतनाम के बौद्ध भिक्षु थिच क्वांग का उदाहरण देती हैं, जिन्होंने 1963 में साइगोन के एक व्यस्त चौराहे पर आत्मदाह कर लिया था, जिसके बाद दक्षिण वियतनाम सरकार की बौद्ध विरोधी नीतियों की दुनिया भर में आलोचना की गई थी। उन्होंने कहा, "यह घटनाएं एक छोटी सी संख्या से शुरू होते हुए अब 120 से ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन पूरी दुनिया अब भी चुप है। यह चुप्पी लोगों को निराश करती है।" वुएजर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एली वीजेल के 1986 के भाषण को उदधृत करती हैं जिसमें उन्होंने एक और समय व जगह की चर्चा की है जहां लोग पीड़ित हैं, लेकिन दुनिया जिसे नजरअंदाज कर रही है: "क्या यह सच है? यह इक्कीसवीं शताब्दी है, कोई मध्य युग नहीं। ऐसे अपराध करने की इजाजत कौन दे रहा है? दुनिया आखिर इस पर चुप कैसे रह सकती है?"

वुएजर ने इस नजरअंदाज करने की वजह को दुनिया में आर्थिक मंदी, घटना के काफी डरावने प्रकृति और दुनिया में चीन के आर्थिक प्रभाव से जोड़ा जिसकी वजह से आत्मदाह एक अरुचिकर सच्चाई बना हुआ है। उन्होंने कहा, "कई देशों का अपना निहित स्वार्थ होता है और इसलिए जब मानवाधिकारों की बात आती है तो वे बिल में घुस जाते हैं।"

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दबाव होने पर ही चीन तिब्बती जनता का दमन बंद करेगा। ◆

सिंह का शर्मनाक जल समझौता

चीन और भारत के बीच एक नए समझौते से अब बीजिंग को साझे संसाधनों पर नियम आधारित सहयोग को संस्थागत रूप देने की जरूरत नहीं रहेगी

ब्रह्मा चेलानी
(दि वाल स्ट्रीट जर्नल, 31 अक्टूबर, 2013)

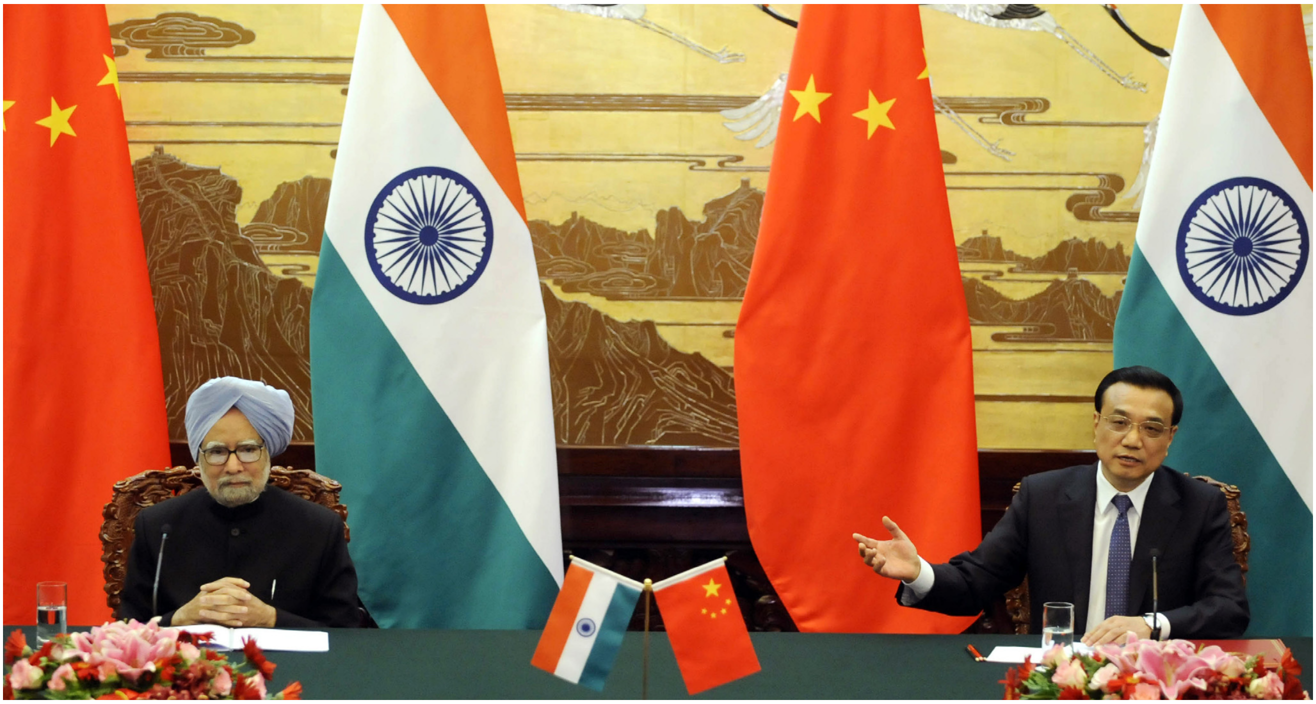

बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में 23 अक्टूबर, 2013 को भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चीनी प्रधानमंत्री ली केक्यांग (दाएं)। फोटोः रायटर्स/क्योदो न्यूज/पेंग सुन/पूल ।

पिछले एक दशक में चीन ने तिब्बत में कई महत्वाकांक्षी बांध परियोजनाओं की पूरी एक श्रृंखला ही चला दी है, जो चीन–भारत संबंधों में अनबन की बड़ी वजह है। पिछले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बीजिंग से एक बहुचर्चित दौरे से लौटे हैं, इस दौरान एक जल सहयोग समझौता भी हुआ है जिसमें नारों और झंकार गीत के अलावा और कुछ नहीं है।

सिंह की यात्रा के दौरान जिस समझौता पत्र पर दस्तखत किए गए हैं, उसमें बस यही कहा गया है कि, "दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि सीमापारीय नदियां और उनसे जुड़े प्राकृतिक संसाधन तथा पर्यावरण भारी महत्व वाली संपदा हैं" और वे "इस बात पर सहमत हुए हैं कि सीमा पारीय नदियों पर सहयोग से परस्पर सामरिक भरोसा और संचार बढ़ेगा।" भारत ने तो "चीन की तारीफ की है कि उसने बाढ़ के मौसम में जल संबंधी आंकड़े मुहैया कराए हैं।" करदाताओं के पैसे से जहाज भर कर पत्रकार ले जाने वाले श्री सिंह ने अपने तुच्छ समझौते को एक बड़ी राजनयिक कामयाबी की तरह पेश किया है। सच तो यह है कि इस समझौते से चीन को भारत की किसी चिंता का समाधान किए बिना एक दुष्प्रचार का बटन मिल गया है।

एशिया में जल की बढ़ती तंगी के बीच चीन ने दुनिया में अतुलनीय जल–विद्युत श्रेष्ठता हासिल कर ली है, एशिया की बड़ी नदियों के उद्‌गम स्थल (तिब्बत पठार) पर ही उनका गला घोंटकर और वह बांधों, बैराज और अन्य ढांचों के द्वारा सीमा पार बहाव को नए सिरे से संचालित करने पर कार्य कर रहा है। असल में किसी भी दूसरे जल–विद्युत दिग्गज की तुलना में चीन में सीमा पार बहने वाली नदियों की संख्या बहुत ज्यादा है।

पूरी दुनिया के बांधों को जोड़ लें तो भी चीन में बनने वाले बाधों की संख्या उनसे ज्यादा है। पिछले एक

दशक में बीजिंग ने आंतरिक नदियों की बजाय अंतरराष्ट्रीय नदियों पर बांध बनाने को ध्यान केंद्रित किया है। इस साल अकेले उसने 54 नए बांध प्रोजेक्ट निर्माण को मंजूरी दी है जो कि मुख्यतः दक्षिण–पूर्व तिब्बत में केंद्रित हैं, इनमें दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया पर बहने वाली नदियों पर बनने वाले बांध भी शामिल हैं।

भारत पर खासकर काफी जोखिम है क्योंकि चीनी क्षेत्र से हर साल बहकर आने वाले 718 अरब क्यूबिक मीटर सतह जल का करीब 48 फीसदी हिस्सा सीधे भारत में ही आता है। इसके अति. रिक्त तिब्बत से निकलकर नेपाल में आने वाली कई नदियां भी गंगा की खाड़ी में आकर मिल जाती हैं। भारत में सिंचित भूमि चीन से ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर भारतीय नदियों का स्रोत चीन नियंत्रित तिब्बत में है।

चीन यदि अपने मौजूदा एकतरफा रास्ते पर चलता रहा तो इसकी ऊपरी जलधाराओं पर स्थित प्रोजेक्ट भारत के बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जल साझेदारी को जटिल बना सकते हैं। वर्ष 1996 के गंगा समझौते में भारत ने बांग्लादेश को यह गारंटी दी है कि कठिन सूखे के मौसम में भी बांग्लादेश के साथ निचली जलधारा में बराबर की साझेदारी करेगा। लेकिन चीन अब गंगा की उन सहायक नदियों पर कई बांध बनाने की तैयारी कर रहा है, जो इस तरह की निचली जलधाराओं का प्रवाह बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वर्ष 1960 का सिंधु समझौता दुनिया का सबसे उदार जल समझौता बना हुआ है जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान को अनंतकाल तक सिंधु जल प्रणाली की छह नदियों का 80.52 फीसदी जल देने पर सहमति जताई है, इस उम्मीद में कि वह जल के इस व्यापार के बदले शांति खरीद सकता है। इन छह नदियों में से दो पर अब चीन बांध बनाने की कोशिश कर रहा है।

नई दिल्ली अब बीजिंग पर यह दबाव डाल रहा है कि वह अपने बांध परियोजनाओं पर पारदर्शिता बरते और यह वायदा करे कि वह किसी भी नदी की दिशा नहीं बदलेगा या सीमा पारीय प्रवाह को कम नहीं करेगा। लेकिन यहां तक कि चीन और भारत के बीच जल संबंधी आंकड़ों में "संवाद और सहयोग" के लिए संयुक्त विशेषज्ञ स्तर की जो प्रणाली वर्ष 2007 में स्थापित हुई है उसका भी कोई खास महत्व नहीं है। चीन ने अपना सहयोग भारत को बाढ़ के मौसम में जल संबंधी आंकड़े बेचने तक सीमित रखा है, दूसरी तरफ भारत साल भर पाकिस्तान को ऐसे आंकड़े मुफ्त में मुहैया करता है। जल युद्ध से बचना है तो इसके लिए नियम आध ारित सहयोग, जल साझेदारी और विवाद निपटान प्रणाली होनी चाहिए। लेकिन चीन ने जल साझेदारी की हर अवधारणा को खारिज किया है और किसी भी पड़ोसी देश के साथ उसने एक भी जल साझेदारी समझौता नहीं किया है। भारत ने निचली जलधाराओं पर स्थित अपने दोनों पड़ोसियों पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऐसे समझौते किए हैं जिनमें समय–समय उठने वाले विवाद को निपटाने में मदद करने की प्रणाली शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस साल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केक्यांग से अलग से हुई मुलाकात में द्विपक्षीय जल समझौते की वकालत की और यह आग्रह किया कि ब्रह्मपुत्र नदी (जो कि तिब्बत से निकलकर पूर्वी भारत होते हुए बांग्लादेश पहुंचती है) की ऊपरी धारा और दक्षिण की ओर बहने वाली अन्य नदियों पर बांध निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम एक संयुक्त आयोग बनाया जाए। भारत फिलहाल चीन द्वारा बांध निर्माण संबंधी गतिविधियों को जानने के लिए हवाई टोह और अन्य खूफिया सूचनाओं पर निर्भर है। सर्वश्री शी और ली ने श्री सिंह के अनुरोध को अनसुना कर दिया।

अब जब देश में नौकरियों की संख्या सर्वकालिक निचले स्तर पर थी और भ्रष्टाचार के मामलों से सरकार घिरी हुई थी, श्री सिंह बीजिंग से खाली हाथ लौटना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया जो चीन देना चाहता था–एक टोकन समझौता जिसमें कोई तत्व नहीं है। बीजिंग आगे से इस समझौते को अपने इस आलोचना की काट की तरह इस्तेमाल करेगा कि वह जल संसाधनों की साझेदारी पर सहयोग करने का इच्छुक नहीं है।

यह समझौता चीन को इस बात के लिए नहीं मना सकता कि वह साझे संसाधनों पर नियम आधारित सहयोग को संस्थागत रूप दे। चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच ऐसे सहयोग कायम करने में विफलता का दीर्घकालिक दुष्परिणाम होगा और इससे चीन एशिया के जल स्रोतों का मालिक बन जाएगा।

चीन के भौगोलिक फायदे और उसकी बढ़ती सैन्य एवं आर्थिक ताकत से भारत के लिए मोलभाव कर सकने की क्षमता सीमित ही रहेगी। इसलिए चीन पर असर डालने के लिए भारत को चीनी माल की भारतीय बाजार में बढ़ती पहुंच का इस्तेमाल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी होगी। हालांकि, पिछले एक दशक में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा समग्र द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में चार गुना तेजी से बढ़ा है। लगातार जारी एकतरफा आर्थिक रिश्ता और चीन द्वारा क्षेत्रीय एवं नदी प्रवाह की यथास्थिति में छेड़छाड़ से भारत पर दोहरी मार पड़ रही है।

चीन में बांध बनाने की लहर इस बात को याद दिलाती है कि तिब्बत अब भी भारत और चीन के बीच विभाजन का केंद्र है। यह विशाल क्षेत्र चीन द्व ारा छह दशक से भी ज्यादा समय पहले चीन द्वारा हड़पे जाने से पहले राजनी. तिक रूप से एक बफर देश हुआ करता था। तिब्बत को चीन एवं भारत के बीच राजनीतिक सेतु बनाने के लिए जल को सहयोग का स्रोत बनाना होगा, संघर्ष का नहीं।

(श्री चेलानी ने हाल में ही "वाटर, पीस ऐंड वारः कन्फ्रंटिंग द ग्लोबल वाटर क्राइसिस" नामक पुस्तक लिखी है) ◆

बीजिंग वाले बड़े भाई की तिब्बत पर है नजर

क्लॉड आरपी
(दि पायोनियर, 24 अक्टूबर, 2013)

चीन के अति दखल वाले जन निगरानी कार्यक्रम से तिब्बत स्वायत्तषासी क्षेत्र में असंतोष की आग भड़क उठी है जिससे स्थानीय जनता और पुलिस के बीच बहुत ज्यादा टकराव होने लगा है। स्थिति उबाल पर है

ल्हासा में तिब्बतियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में गश्त करते चीनी सुरक्षा बल के जवान।

हाल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आलेख छापा था, "चीन के धन से कौन डरता है?" इस आलेख के लेखक जोनाथन मिरस्की वर्ष 1991 के शरद ऋतु में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर से जुड़ी एक घटना की चर्चा करते हैं जो टिनामेन चौक की घटना के बाद चीन जाने वाले पहले पश्चिमी नेता थे। मेजर ने मीडिया से कहा था कि वह एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा तैयार कई सौ राजनीतिक कैदियों की एक सूची चीनी नेतृत्व को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री ली पेंग से मुलाकात के बाद मेजर ने प्रेस से इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अपने चीनी समकक्ष को उक्त सूची सौंप दी है। इसके बाद हर किसी ने मेजर के नैतिक साहस की तारीफ की। लेकिन इसके बाद मिरस्की को इस मुलाकात के दौरान उप. स्थित रहे एक ब्रिटिश अधिकारी से पता चला कि मेजर ने ली पेंग को कोई सूची नहीं दिखाई थी और न ही उन्होंने मानवाधिकार के बारे में एक भी शब्द बोला था, मीडिया से उन्होंने सफेद झूठ बोला था। कारोबार तो आखिर कारोबार होता है।

इसलिए यह उम्मीद तो न करें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीनी नेताओं से तिब्बत के घटनाक्रम के बारे में कोई सवाल करेंगे, तथाकथित भविष्य की आर्थिक कारोबारी संभावनाएं भारत के लिए ज्यादा महत्व रखती हैं। हालांकि, यह सच है कि तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति काफी दयनीय है। वास्तव में आज हालत जितनी बुरी है, उतनी 2008 से अब तक कभी नहीं रही है।

नागक्यू का मामला दिलचस्प हैः कम्युनिस्ट पार्टी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल (श्री यु झेंगसेंग सहित जो तिब्बत मामले के प्रभार के मामले में पार्टी में चौथा स्थान रखते हैं) के कई 'जांच दौरे' के बावजूद यह प्रशासनिक क्षेत्र उबाल पर है, बताया जा रहा है कि वहां बहुत से तिब्बती चीनी सुरक्षा बलों की गोलियों से मारे गए हैं। नागक्यू तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के सात प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। यह सबसे बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 4,50,537 वर्ग किमी और जनसंख्या चार लाख है। क्विंघई–तिब्बत रेलमार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरती है जिसके नाते चीन की योजना इसे तिब्बत पठार के मुख्य आर्थिक केंद्र में बदलने की है–स्थानीय जनता की परवाह किए बिना।

मई महीने में श्री यू ने तिब्बत पर गठित एक छोटे समूह के बैठक की अध्यक्षता की, यह समूह बीजिंग में चीन की तिब्बत नीति को लागू करता है। इस बैठक में तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र और गांसू, क्विंघई,

यून्नान, सिचुआन प्रांतों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद इन इलाकों के पार्टी सचिव अपने संबंधित प्रांत में गए और उन्होंने 'जनता' को श्री यु के निर्देशों के महत्व पर उपदेश दिए। टीएआर के पार्टी सचिव श्री छेन कुआंगुओ श्री यू का "स्थिरता एवं सौहार्द् कायम करने का संदेश लेकर नागक्यू प्रशासनिक क्षेत्र गए। दुर्भाग्य से सचिव छेन जब ल्हासा लौट रहे थे उसी दिन नागक्यू के एक काउंटी ड्रिरू में हजारों तिब्बती जमा हो गए। वे ड्रिरू काउंटी में खनन प्रोजेक्ट शुरू करने की सरकार की योजना के खिलाफ प्रदर्शन के लिए एक पवित्र पर्वत पर इकट्ठा हुए। नागल्हा जाम्भा नाम का यह पर्वत खनिज संसाधनों के लिहाज से समृद्ध है। गत 24 मई को करीब 1,000 पिकअप वाहनों में भरकर 5,000 से ज्यादा तिब्बती इस पवित्र स्थल पर जमा हो गए और उन्होंने चीनी कंपनियों द्वारा किए जा रहे अंधाधुंध खनन कार्य को रोकने लिए कहा। साफतौर पर तत्काल तो तिब्बती अस्थायी रूप से खनन कार्य रोकने में सफल हो गए, लेकिन वहां स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई।

अक्टूबर 2012 में दो तिब्बती चचेरे भाई 20 वर्षीय सेपो और 25 वर्षीय तेनजिन ने ड्रिरू में एक स्कूल के सामने आत्मदाह कर लिया था। इन भाइयों ने खुद को आग लगाने से पहले तिब्बत को आज़ादी देने और तिब्बती आध्यात्मिक नेता परमपावन दलाई लामा को वापस लाने की मांग की। उन्होंने अनुरोध किया कि सभी तिब्बती "भाइयों की तरह एक रहें।" उनमें इस बात को लेकर असंतोष था कि उस इलाके में 'जनता के फायदे के लिए बुनियाद मजबूत करें', 'ग्रिड प्रबंधन प्रणाली' 'नए समाजवादी गांव' जैसे कई निगरानी अभियान चलाए जा रहे थे जो लोगों के निजी जीवन में भारी दखल देने वाले थे। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते थे उनको बुरी तरह पीटा जाता है और सजा दी जाती थी।

इसके एक साल बाद गत 28 सितंबर को ड्रिरू काउंटी के मोवा गांव मे स्थानीय तिब्बतियों और चीनी सुरक्षा बलों के बीच गंभीर टकराव हुआ। असल में तिब्बती ने एक नए अभियान 'नौ चीजें जरूर होनी चाहिए' के खिलाफ विद्रोह कर दिया जिसके तहत कई अन्य चीजों के अलावा सभी लोगों को अपने घरों पर चीन का लाल राष्ट्रीय झंडा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जब स्थानीय तिब्बतियों ने इससे इनकार किया तो तत्काल ही जन सशस्त्र पुलिस के जवान वहां पहुंच गए। इससे टकराव अपरिहार्य हो गया। ड्रिरू काउंटी में स्थानीय प्रशासन ने घोषणा किया कि जो तिब्बती आधिकारि नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें सजा दी जाएगी।

तिब्बती विरोध प्रदर्शनकारियों के बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया, उनके बीमार परिजनों का अस्पताल में इलाज करने से मना कर दिया गया और उन्हें प्रसिद्ध ओफियोकॉर्डीसेप्स सिनेन्सिक के पैदावार के लिए लाइसेंस देने से मना कर गया, यह एक कीमती फंगस होता है जिसका चीन में कामोत्तेजक दवाएं बनाने में इस्तेमाल होता है।

इसके कुछ हफ्तों पहले ही, तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के प्रशासन ने ड्रिरू में 18,000 चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजा था ताकि वे पार्टी की 'जनपक्षधर' नीति को आगे बढ़ा सकें। इन कार्यकर्ताओं ने स्थानीय तिब्बतियों के बीच 'देशभक्ति शिक्षा' के अभियान चलाए और उनसे कहा कि वे पार्टी और देश के प्रति 'प्यार और कृतज्ञता' दिखाएं।

गत 29 सितंबर को एक और विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें ड्रिरू काउंटी के प्राइमरी और मिडल स्कूलों के 4000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इन विद्यार्थियों को जब यह पता चला कि उनके उन सहपाठियों को स्कूल से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है जिनके मां–बाप ने पहले विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था तो सभी गुस्से में आ गए और सड़कों पर उतर पड़े। इसके बाद काउंटी के मिडल स्कूल को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया।

राष्ट्रीय दिवस (2 अक्टूबर) के एक दिन बाद ड्रिरू काउंटी के स्थानीय तिब्बती एक बार फिर सुरक्षा बलों को ललकारते हुए बड़े राजमार्गों को जाम कर दिया जहां सुरक्षा बलों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। इस बार विरोध प्रदर्शन तिब्बती की पहचान खत्म करने के खिलाफ था। इस विरोध प्रदर्शन में चार तिब्बतियों के मारे जाने की खबर है।

तिब्बत में 'निगरानी' गतिविधि किस कदर चलाई जा रही है इसका अंदाजा चीनी समाचार एजेंसी शिनहुआ की हाल की उस स्वीकारोक्ति से मिल जाता है जिसमें उसने यह स्वीकार किया है कि पिछले दो साल में टीएआर के 5,459 गांवों और 1,877 मठों में 60,000 काडर की तैनाती की गई है। टीएआर में पार्टी के कार्यकारी सचिव श्री वु यिंगजी हान चीनी हैं और तिब्बत में कार्य करने का उन्हें 39 वर्षों का अनुभव है। वह पिछले कुछ हफ्तों से नागक्यू में अभियान चला रहे हैं। तथ्य यह है कि केंद्रीय नेतृत्व को जिस तरह से इतने लंबे समय के लिए श्री वु को नागक्यू में रखना पड़ा है उससे यह साफ होता है कि परिस्थिति गंभीर तरीके से नियंत्रण से बाहर है।

हालात कितने बदतर हैं, चीनी सुरक्षा के नए मुखिया जन सुरक्षा मंत्री गुओ शेंगकुन को बीजिंग से उड़कर ल्ह. ासा पहुंचना पड़ा, नवीनतम हालात का जायजा लेने के लिए। अपनी इस यात्रा के दौरान (10 अक्टूबर को उनके बीजिंग लौ. टने के बाद ही इसकी घोषणा की गई) श्री गुओ ने "तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करने का आह्वान किया ताकि क्षेत्र के तीव्र आर्थिक विकास की गारंटी हो सक. े।" शिनहुआ के अनुसार श्री गुओ ने "पुलिस गश्ती का कार्य जांचने, अपराध और अपराध के मामलों को किस तरह से हल किया जा रहा है, अग्निशमन कार्य और जन सेवा कार्यों का निरीक्षण करने के लिए थानों का दौरा किया।"

आखिर कितने लंबे समय तक परिस्थिति खराब होती जाएगी? शायद अब इसका समय आ गया है कि कम्युनिस्ट पार्टी प्रशासन कुछ अलग हटकर सोचे और तिब्बत को शांत करने के लिए दलाई लामा की सेवाएं लें। यह कम्युनिस्ट शासन के लिए एक बड़ा कदम होगा। यही एक मात्र समाधान है जिसे अपनाने में समझदारी है। ◆

तिब्बती कवयित्री ने बताया कि आखिर क्यों कर रहे हैं तिब्बती आत्मदाह

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 18 अक्टूबर, 2013)

तिब्बत में 120 से ज्यादा तिब्बतियों ने चीनी शासन के खिलाफ आत्मदाह रूपी विरोध प्रदर्शनों का सहारा क्यों लिया है, इसकी आम वजह सबको पता है: इनमें से ज्यादातर ने आज़ादी देने और दलाई लामा को निर्वासन से वापस लाने के नारे लगाए थे। लेकिन वह ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां क्या थीं जिसकी वजह से इन सबने चीनी शासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर करने के लिए सबसे पीड़ादायी और खुद को मिटा देने का यह तरीका अपनाया? प्रख्यात तिब्बती कवयित्री, निबंधकार और तिब्बत में चीनी नीतियों की मुखर विरोधी सुश्री सेरिंग वुएजर ने पेरिस में प्रकाशित अपनी एक नई पुस्तिका में इस पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है।

इस पुस्तिका, "तिब्बत में आत्मदाह: दुनिया के लिए शर्म" में विद्रोही चीनी कलाकार अइ वुइवुइ के चित्र भी हैं और यह अभी सिर्फ फ्रेंच भाषा में प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक का लोकार्पण पेरिस में गत 17 अक्टूबर को किया गया। वुएजर बीजिंग में सरकारी निगरानी में रहती हैं, लेकिन तिब्बती इलाकों में उनका संपर्कों का जाल है। इस पुस्तिका में वुएजर ने उस वजह की जड़ तक जाने की कोशिश की है कि आखिर क्यों 120 से ज्यादा तिब्बतियों ने हाल के वर्षों में आत्मदाह किया है। एएफपी की 17 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार वुएजर ने इस पुस्तक में लिखा है, "अनशन विरोध प्रदर्शन का दुनिया भर में स्वीकार्य और सम्मानजनक तरीका है, लेकिन आत्मदाह को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है क्योंकि इसमें सीमा से बाहर पीड़ा होती है और इसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर पाते।" उन्होंने लिखा है, "आत्मदाह सबसे ज्यादा चोट करने वाली चीज जो ये अलग–थलग पड़ चुके विरोध प्रदर्शनकारी कर सकते हैं, अहिंसा के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए।" इस पुस्तिका में चीन जनवादी गणतंत्र के तिब्बती इलाकों को एक विशाल कारागार बताया गया है जो "सशस्त्र सैनिकों और हथियारों से लैस वाहनों से भरा हुआ है।"

उनका कहना है कि आत्मदाह के पीछे कई तरह की वजहें हैं–प्रशासन के लोग दलाई लामा के उपदेश वाले वीडियो देखने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं, खदान और बांध बनाने के लिए नौमड्स को जबरन उनके चारागाह से बाहर किया जा रहा है, मठों में निगरानी कैमरे लगाए जा रहे हैं और ऐसे कई अन्य कार्य।

उन्होंने बताया कि आत्मदाह विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग किसी एक विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र से आते हैं, जिनमें भिक्षु और भिक्षुणी, दो स्कूल जाने वाली लड़कियां, तीन छात्र, तीन श्रमिक, चार खुदरा दुकानदार, एक बढ़ई, एक ब्लॉगर, एक तांगका (परंपरागत तिब्बती पेंटिंग) कलाकार, एक टैक्सी ड्राइवर, कम्युनिस्ट पार्टी के एक रिटायर्ड पदाधिकारी शामिल हैं।

करीब 47 साल की वुएजर, जो तिब्बती–चीनी दोनों वंश से जुड़ी हैं, तिब्बतियों में अपने ब्लॉग के लिए काफी प्रसिद्ध हैं जिन पर वे कविताएं और निबंध लिखती हैं। उन्हें करीब चार साल तक सख्त पुलिस पहरे में रखा गया है, लेकिन फिलहाल उन्हें थोड़ी आज़ादी है और अब वह देश में कहीं भी आ–जा सकती हैं। हालांकि, उनका मानना है, "इस तरह की पुस्तक लिखना... निश्चित रूप से खत. रनाक है। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि यह कितना खतरनाक है।"

उन्होंने कहा, "मुझ पर हर दिन, चौबीसों घंटे गहरी नजर रखी जाती है।" उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने तीन–चार कार में भरे सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रहती है, उनकी घर के छत पर एक कैमरा लगाया गया है और सुरक्षा बल हर कदम पर उनके पीछे रहते हैं। ◆